इकाई 16 लैटिन अमेरिका में क्षेत्रीयतावाद

इकाई की रूपरेखा

16.1 प्रस्तावना

16.2 लैटिन अमेरिका में क्षेत्रीयतावाद का विकास

16.2.1 लैटिन अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन (LAFTA)

16.2.2 ऐंडियन समझौता

16.2.3 केन्द्रीय अमेरिकी साझा बाज़ार (CACM)

16.2.4 कैरिबियाई समुदाय (CARICOM)

16.3 पारम्परिक क्षेत्रीयतावाद की विफलता और नए क्षेत्रीयतावाद की ओर प्रस्थान

16.3.1 मरकोसुर

16.4 गोलार्ध एकीकरण

16.4.1 उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र (नाफटा)

16.4.2 अमेरिकास का मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTAA)

16.4.3 अमेरिकी राज्यों का संगठन (OAS)

16.5 सारांश

16.6 अभ्यास प्रश्न

16.1 प्रस्तावना

लैटिन अमेरिकी देशों की कई आर्थिक विशेषताएँ हमें इस क्षेत्र को एक उप-महाद्वीप के रूप में देखने का मौका देती हैं। फिर क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है।

अन्य आर्थिक क्षेत्रों की तुलना में, लैटिन अमेरिका का हिस्सा विश्व व्यापार में बहुत कम है। 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान का विश्व व्यापार में 60 प्रतिशत हिस्सा था, जबकि लैटिन अमेरिका का विश्व व्यापार में हिस्सा निर्यात में 4.5 प्रतिशत और आयात में 5.2 प्रतिशत था। इन आँकड़ों से इस क्षेत्र में आयात और निर्यात में एक असंतुलन भी दिखाई देता है। 1980 के दशक से निर्यात की अपेक्षा आयात में अधिक बढ़ोतरी हुई है। इसके कारण क्षेत्र के अधिकांश देशों में भुगतान संतुलन की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है।

लैटिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था अधिकतर कृषि और खनन उत्पादों पर टिकी है। वहाँ से होने वाले निर्यातों में लगभग एक चौथाई हिस्सा इन उत्पादों का होता है जहाँ पर व्यापार की दिशा का सवाल है, तो इसका मुख्य लक्ष्य (लगभग 50 प्रतिशत) संयुक्त राज्य अमेरिका होता है।

बहुराष्ट्रीय व्यापार ढाँचे की एक उल्लेखनीय विशेषता अस्तित्व में आए व्यापारिक और आर्थिक शासनों की भरमार रही है। गैट अथवा विश्व व्यापार संगठन (GATT/WTO – World Trade Organisation) के तत्वाधान में जो यह नया रूझान सामने आया है, उसे 1980 के दशक के व्यापारिक क्षेत्रीयतावाद और 1950 के दशक के संरक्षणवादी और औद्योगिक क्षेत्रीयतावाद के बाद क्षेत्रीयतावाद की तीसरी लहर के रूप में देखा जा सकता है।

क्षेत्रीयतावाद का यह नया संस्करण इस मायने में अनूठा है क्योंकि यह भूमंडलीकरण की शक्तियों के

अनुरूप है। भूमंडलीकरण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि अलग-अलग राज्यों की आर्थिक नीतियाँ भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में उनकी स्थिति को ध्यान में रखकर तय की जाती हैं। यह बात आज के क्षेत्रीयतावाद पर भी सही बैठती है – जहाँ राज्य भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति दृढ़ करने के लिए अपनी आर्थिक नीतियों में तालमेल करते हैं।

इस प्रकार, क्षेत्रीय एकीकरण को भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण की दिशा में उठाए गए एक कदम के रूप में देखा जाता है। भूमंडलीय स्तर पर सीधे भागीदारी करना अधिकांश देशों के लिए कठिन होता है, इसलिए क्षेत्रीय रास्ते के माध्यम से हाशियाबंदी से बचा जाता है।

आज क्षेत्रीयतावाद में राजनीतिक और आर्थिक दोनों पहलू शामिल होते हैं। राजनीतिक एकीकरण के उपायों को आर्थिक एजेंडे को मज़बूत करने और इसे और भी अधिक बाध्यकारी बनाने के लिए लागू किया जाता है। यह बहुआयामी चरित्र आज समूहों की लंबी उम्र का एक कारण है। जब समूह एक अकेले मुद्दे पर आधारित होते हैं, तो किसी भी सदस्य के लिए उससे बाहर जाना आसानतर होता है। जहाँ कई मुद्दे होते हैं, वहाँ समूह से हटना अधिक महँगा पड़ता है।

यह नया क्षेत्रीयतावाद अपने पुराने संस्करणों से इस मायने में भिन्न है कि यह गैट के नियमों के अनुरूप है। नया क्षेत्रीयतावाद 'मुक्त क्षेत्रीयतावाद' और 'गहन एकीकरण' जैसी अन्य अवधारणाओं से संबंधित है। जहाँ पहली अवधारणा गैट के साथ अपनी अनुकूलता को व्यक्त करती है, वहीं 'गहन एकीकरण' की अवधारणा आर्थिक उदारवाद को क्षेत्रवार क्रम में देखते हुए मुक्त व्यापार के मुद्दों से परे जाने के उसके उद्देश्य को परिलक्षित करती है।

फिशलो और हैगर्ड के अनुसार क्षेत्रीयतावाद को क्षेत्रीयकरण से अलग रखकर देखना चाहिए। क्षेत्रीयकरण तो आर्थिक संसाधनों के प्रवाह का क्षेत्रीय जमाव है। वहीं क्षेत्रीयतावाद वह प्रक्रिया है जिसका एक मज़बूत राजनीतिक आधार है, और इसमें सहभागी देशों के बीच आर्थिक नीतियों का समन्वय शामिल है। क्षेत्रीयतावाद को सामान्यतया अधिमानी व्यापार करारों (preferential trading agreements – PTA) के माध्यम से व्यवहार में लाया जाता है। अधिमानी व्यापार करारों के निम्नलिखित घटक हो सकते हैं: (क) सीमा शुल्क संघ – ये संघ आंतरिक व्यापार के अवरोधों को समाप्त कर एक समान बाहरी प्रशुल्क ((commonexternal tariff – CET) लागू करवाते हैं; (ख) मुक्त व्यापार क्षेत्र (free trade areas – FTA) - ये भी सीमा शुल्क संघों की तरह होते हैं; किन्तु इनमें एक समान बाहरी प्रशुल्क (सी ई टी) नहीं होता; और (ग) साझा बाज़ार – ये राष्ट्रीय सीमाओं के पार आर्थिक संसाधनों के मुक्त प्रवाह की छूट देते हैं।

नव-उदारवादी आर्थिक व्यवस्था और भूमंडलीकरण के संदर्भ में, क्षेत्रीय एकीकरण का अर्थ अब पहले से बहुत भिन्न हो गया है। लैटिन अमेरिका के लिए क्षेत्रीयतावादी कार्यक्रम की जड़ों के कई कारण हैं – आर्थिक कारण, वैश्विक आर्थिक में हाशियाबंदी से बचना; और राजनीतिक कारण, क्षेत्र में शान्ति और लोकतन्त्र को मज़बूत करना।

16.2 लैटिन अमेरिका में क्षेत्रीयतावाद का विकास

लैटिन अमेरिका में आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय पहल ने पिछली लगभग एक शताब्दी में एक लंबा रास्ता तय किया है। इस समय 21वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में, क्षेत्रीयतावाद की ओर नये सिरे से बने, और बढ़ते रूझान को देखा जा सकता है; यद्यपि इस बीच अनेक देशों ने कुछ गंभीर आर्थिक झटके भी झेले हैं, जिसमें 1982 का मैक्सिको का ऋण संकट अग्रगामी था।

शीत युद्ध की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी भूमिका

निभाई कि कोई भी अर्थपूर्ण प्रक्रिया सफल नहीं होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव ने कई तरीकों से इस तरह की पहलों का निषेध किया। किन्तु, 1980 के दशक तक, भूमंडलीय वातावरण महत्वपूर्ण और दूरगामी बदलावों का सहचर था, जिसके चलते क्षेत्रीय कार्यक्रमों को विचार-विनिमय के लिए फिर से रखा जा सका।

16.2.1 लैटिन अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन - लाफ्ता (LAFTA)

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में, यूरोप में अनेक क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की गई, जिनका उद्देश्य विशेषकर फ्रांस और जर्मनी के बीच शान्ति की नींव रखना था। इन संगठनों - यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय (1951) और यूरोपीय आर्थिक समुदाय (1951) का आर्थिक आधार मुक्त व्यापार नमूना था।

इसी प्रकार, लैटिन अमेरिका में क्षेत्रीय सहयोग की ओर पहले कदम में भी उदारवादी आर्थिक मुक्त व्यापार के इसी ढाँचे को अपनाया गया। यह लैटिन अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन - लाफ्ता (Latin American Free Trade Association – LAFTA) था, जिसका गठन 1960 की मांटोविडियो संधि के फलस्वरूप हुआ। इसमें अर्जेन्टीना, ब्राज़ील, मैक्सिको, पेरू, पेरुग्वे, चिल्ली, उरुग्वे, और अंत में वेनेज़ुएला, कोलोम्बिया, बोलिविया और इक्वाडोर शामिल हुए। यह अपेक्षा की गई थी कि लैटिन अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन इस तर्क का अनुसरण करेगा तो राष्ट्रों को क्षेत्रीय एकीकरण के माध्यम से एक अधिक बड़े बाज़ार से लाभ उठाने में मदद मिलेगी क्योंकि इस बाज़ार के लिए उत्पादन करने में वे मापक्रम (स्केल) की अर्थव्यवस्थाओं का लाभ उठा पाएँगे।

लैटिन अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन (लाफ्ता) कई कारणों से कोई ठोस आकार नहीं ले पाया। इनमें सबसे महत्वपूर्ण कारण था समूह का आकार।

लैटिन अमेरिका में आयात स्थानापन्न औद्योगीकरण (आई एस आई) की नीति ने 1960 के दशक में जड़े जमा ली थीं। इस नीति में सरकारी मदद के बदले पर घरेलू उद्योग के सभी स्तरों को मज़बूत करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया। अन्य क्षेत्रों के देश - जैसे पूर्व एशिया में दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान – किसी न किसी रूप में इस दृष्टिकोण पर पहले ही चल रहे थे, भले ही वह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहमति से रहा हो। लैटिन अमेरिका में, आयात स्थानापन्न औद्योगीकरण (आई एस आई) ने वामपंथी रूझान वाली विचारधाराओं को अपनाया। इस संदर्भ में निर्भरता आन्दोलन सर्वाधिक उल्लेखनीय है।

आयात स्थानापन्न औद्योगीकरण (आई एस आई) के परिणतिस्वरूप संरक्षणवादी उपायों में बढ़ोतरी हो गई। किन्तु, क्षेत्र की अलग-अलग अर्थव्यवस्थाएँ अपने आप में इतनी बड़ी नहीं थी, और न ही उनके पास ऐसी अन्तर्मुखी नीतियों को चलाए रखने के लिए पर्याप्त संसाधन ही थे। आयात स्थानापन्न औद्योगीकरण (आई एस आई) की विफलता ने क्षेत्रीय सहयोग को देखने का तरीका भी बदल दिया। औद्योगीकरण का ध्येय तो बना रहा, किन्तु यह भी समझ में आ गया कि यह तब तक संभव नहीं होगा, जब तक देश अपने बाज़ारों का एकीकरण नहीं कर देते। उद्देश्य अब मात्र मुक्त व्यापार समझौतों से बढ़कर राज्य के समर्थन से विकास और क्षेत्रीयतावाद को प्राप्त करना हो गया। लैटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक आयोग और उसके निदेशक राऊल प्रेबिस्क ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

16.2.2 ऐंडियन समझौता

इस नए चिंतन को 1969 की ऐंडियन संधि अथवा कार्टेन्या समझौते में ठोस आकार मिला। इस संधि

पर बोलिविया, वेनेज़ुएला, पेरू, चिल्ली, कोलोम्बिया और इक्वाडोर ने हस्ताक्षर किए। इसमें भूमंडल के उत्तरी-दक्षिणी विभाजन और लैटिन अमेरिका की क्षेत्रीय असमानताओं पर चिंता व्यक्त की गई। छोटे देशों में इस बात को लेकर रोष था कि लैटिन अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन (लाफ्ता) के तहत अर्जेन्टीना, औद्योगिक और मैक्सिको जैसे बड़े देशों को असमान लाभ पहुँचाया जा रहा था।

जहाँ लाफ्ता का आधार मुक्त व्यापार नमूना था, वहीं ऐंडिय समझौते का झुकाव वामपंथ की ओर था। निर्भरता के संप्रदाय से प्रेरित, इस समझौते का उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य विकसित देशों की नकल करना था, जो अर्थव्यवस्था पर राज्य के नियंत्रण के बल पर इस स्थिति पर पहुँचे थे। अब जो भी क्षेत्रीय प्रयास किए गए वे विदेश-विरोधी पूंजीगत पूर्वग्रह से ग्रस्त थे।

16.2.3 केन्द्रीय अमेरिकी साझा बाज़ार (CACM)

केन्द्रीय अमेरिकी साझा बाज़ार (Central Amercia Common Market – CACM) की स्थापना एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरस और निकारागुआ के बीच 1960 में हुई मानागुआ की संधि का परिणाम था। कोस्टा रीका 1962 में इस संधि में शामिल हुआ। इस संधि में 1958 की बहुपक्षीय संधि और अन्य द्विपक्षीय समझौतों की सिफारिशों को शामिल किया गया। स्वाधीनता के बाद से सभी केन्द्रीय अमेरिकी राज्य एक अलग राजनीतिक इकाई – केन्द्रीय अमेरिकी संघीय गणराज्य – का गठन कर चुके थे। इसके विघटन के बाद से पाँचों राज्यों को संबद्ध करने की कई कोशिशें हो चुकी हैं क्योंकि वे एक जैसे हैं और एक सुगठित और सघन भौगोलिक इकाई की रचना करते हैं।

इस संधि में शामिल राज्यों को एक सीमित संख्या को छोड़ शेष सभी सामानों पर से अंतः क्षेत्रीय व्यापार के लिए प्रशुल्क समाप्त कर देने का कहा गया। उनमें एक साझा बाह्य शुल्क (सी ई टी) लगाने को कहा गया। आयात स्थानापन्न औद्योगीकरण (आई एस आई) इसलिए विफल हो गया क्योंकि देशों के पास अंतर्मुखी नीतियों को चालू रखने लायक संसाधन नहीं थे। कुछ लोगों ने भुगतान संतुलन की कठिनाइयों को व्यापारिक उदारीकरण की प्रगति का कारण बताया। कुछ और कारण भी थे जो केन्द्रीय अमेरिकी साझा बाज़ार (सी ए सी एम) से संबद्ध नहीं थे, और इनकी परिणति एल सल्वाडोर और होंडुरस के बीच हिंसा में हुई।

16.2.4 कैरिबियाई समुदाय (CARICOM)

कैरिबियाई समुदाय (Caribbean Community – CARICOM) कैरीकॉम 1973 की चागुआरमास की संधि के फलस्वरूप अस्तित्व में आया। कैरीकॉम उस कैरिबियाई मुक्त व्यापार संघ अर्थात् कैरिफ्टा (CARIFTA) का ही विस्तार है जिसका गठन 1965 में एंटीगुआ, बारबाडोस, बेलीज़, डोमिनकन रिपब्लिक, ग्रेनाडा, गुयाना, जमैका, मांटसेराट, सेंट किट्स नेविस, एंगीला, सेंट लूसिया, सेंट विन्सेंट और त्रिनिडाड और टोबैगो के बीच हुई संधि के फलस्वरूप हुआ था। साझा बाज़ार का मतलब होता था व्यापार का उदारीकरण और एक समान बाहरी शुल्क (सी ई टी) को लागू करना। छोटे सदस्यों को प्रशुल्क समाप्त करने के लिए और अधिक समय दिया गया।

यह भी सफलता नहीं थी। सदस्य देश फिर भी औद्योगिक राज्यों के साथ व्यापार पर बहुत निर्भर रहे और सदस्य राज्यों के बीच आर्थिक नीतियों में अंतर था।

16.3 पारम्परिक क्षेत्रीयतावाद की विफलता और नए क्षेत्रीयतावाद की ओर प्रस्थान

किन्तु 1970 के दशक तक यह स्पष्ट हो चुका था कि क्षेत्रीय एकीकरण का यह दूसरा प्रयास भी

विफल रहा था। आर्थिक राष्ट्रवादी नीतियों में लैटिन अमेरिका के लिए एक साझा बाज़ार की स्थापना का निषेध कर दिया गया था। अस्सीवें दशक के प्रारंभ में इस प्रक्रिया को शुरू करने के परिणामस्वरूप लैटिन अमेरिकी एकीकरण संगठन (Latin American Integration Association – LAIA) अस्तित्व में आया। किन्तु इस प्रयास के पीछे आर्थिक उद्देश्य नहीं थे। उस समय की तनावपूर्ण भू-राजनीतिक स्थिति के चलते इस कार्यक्रम में क्षेत्र की रणनीतिक वास्तविकताओं को अधिक स्थान मिला।

उस समय की अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति क्षेत्रीय एकीकरण के उद्देश्य के अनुकूल नहीं थी। 1982 के ऋण संकट का सहयोग की संभावना को नुकसान पहुँचाने में काफी योगदान रहा। दो विशाल महाद्वीपीय देशों, अर्जेन्टीना और ब्राज़ील के बीच सम्बंध खराब होने से भी इस क्षेत्र में प्रगति नहीं हो पाई।

अर्जेन्टीना और ब्राज़ील के बीच चली आ रही शत्रुता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अधिकांश वर्षों तक तो शांत रही, किन्तु 1980 के दशक के प्रारंभ में फिर उभर आई। अर्जेन्टीना में यह भय पहले से ही बना हुआ था कि ब्राज़ील के उत्पाद उसके बाज़ारों में छा रहे थे। सशस्त्र टकराव की संभावना भी देखी जा रही थी। इस तथ्य से भी कोई लाभ नहीं हुआ कि दोनों ही देशों में सैनिक सरकारें थीं/ फॉकलैण्ड/मालविनास प्रकरण में अर्जेन्टीना की प्रादेशिक महत्वाकांक्षाओं का संकेत देखा गया। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और दोहन में भी शत्रुता के लक्षण देखे गए। केन्द्रीय और दक्षिणी अमेरिका के कई देशों ने इस क्षेत्र में तेल, पानी, मछली भंडार और खनिज संसाधनों पर अपना दावा ठोंक दिया था।

यही नहीं केन्द्रीय अमेरिका में हिंसा और गृह युद्ध फैल गया और इसका सीधा सम्बंध क्षेत्र में महाशक्तियों की और भी अधिक प्रतिद्वंद्विता से था। लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में, प्रतिरक्षा व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई जिससे आर्थिक विकास बाधित हो गया।

क्षेत्रीय समझ बनाने के दिशा में कदम उठाए गए। विशेषकर केन्द्रीय अमेरिका में कोंटाडोरा समूह (वेनेज़ुएला, मैक्सिको, कोलंबिया और पनामा) और एरकीपुलास समझौते ने इस कलहग्रस्त क्षेत्र में शान्ति की दिशा में काम किया। इसी रूझान का विस्तार 1980 के दशक के मध्यम में अर्जेन्टीना और ब्राज़ील के बीच सम्बंधों में देखने को मिला। 'एकीकरण और सहयोग कार्यक्रम' (Integration and Cooperation Programme – PICAB, 1980) और 'एकीकरण और सहयोग संधि' (1989) इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे। एकीकरण और सहयोग कार्यक्रम ने कई द्विपक्षीय प्रोटोकॉल स्थापित किए, जबकि 1989 की संधि में एक दशक में दोनों के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का संकल्प लिया गया।

राजनीतिक तनाव कम हुए तो अर्जेन्टीना और ब्राज़ील के बीच आर्थिक सहयोग को भी प्रोत्साहन मिला। ब्राज़ील के परमाणु कार्यक्रम में आई रुकावट से भी अर्जेन्टीना में भय कम हुआ। परमाणु प्रौद्योगिकी को अब दीर्घकालीन आर्थिक विकास के साधन के रूप में देखा जाने लगा, इसके सैनिक लाभ तो थे ही। इस प्रकार, परमाणु कार्यक्रम में सहयोग और पारदर्शिता ने भरोसा कायम करने की दिशा में कुछ काम तो किया ही, ये विश्वास बनाने के अत्यंत कारगर उपाय भी रहे।

दक्षिणी अमेरिका में आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में अर्जेन्टीना और ब्राज़ील अभिन्न रहे हैं। इन दोनों देशों में मैत्री सम्बंधों का होना इस क्षेत्र में सहयोग के लिए अनिवार्य है। अस्सी के दशक तक, साझा बाहरी दबावों और वैकल्पिक नीतियों के अभाव के परिणामस्वरूप उनकी विदेश नीतियों में समरूपता आई।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के समय में, अर्जेन्टीना और ब्राज़ील (और क्षेत्र के कई अन्य देशों) ने एक नीति का अनुसरण किया था जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव से दूर हटने और विकासशील

तथा विकसित दुनिया की बड़ी शक्तियों से निकट के सम्बंध बनाने का प्रावधान था। किन्तु अमेरिका के निषेध की यह रणनीति कारगर नहीं हो पाई क्योंकि क्षेत्र में वाशिंगटन का प्रभाव और संलिप्तता उसके साम्यवाद-विरोधी कार्यक्रम के अंग के रूप में बनी रही। इस प्रकार, लैटिन अमेरिकी देशों के लिए अगला कदम रहा एक साझा मंच और क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से उन्हीं नीतियों का अनुसरण करना।

इस प्रकार, बाहरी दबावों के खिलाफ एकजुट होने की इच्छा के परिणामस्वरूप ही आर्थिक सहयोग की स्थिति बनी। अस्सी के पूरे दशक में आर्थिक गिरावट ने इस स्थिति से मिलकर निपटने की आवश्यकता भी खड़ी कर दी। कम से कम अर्जेन्टीना और ब्राज़ील के बीच, आर्थिक सहयोग में घरेलू आर्थिक नीतियों की समरूपता से मदद मिली; ब्राज़ील में क्रूसादो योजना थी तो अर्जेन्टीना में ऑस्ट्रल योजना।

क्षेत्र के भीतर राजनीतिक स्थितियों में बदलाव के चलते भी कुछ देशों को परस्पर अमेरिका से सहयोग करना पड़ा। अर्जेन्टीना और चिल्ली के बीच तनाव, ऐंडियन क्षेत्र में गुरिल्ला हिंसा, और क्यूबा, सूरीनाम तथा ग्रेनाडा के अस्थिर कैरिबियाई क्षेत्रों से विध्वंस के भय के साथ ही ब्राज़ील के प्रति अर्जेन्टीना का खतरा भी कम रहा। इन मिली-जुली बदली परिस्थितियों ने क्षेत्रीय सहयोग में भी मदद की।

फिर, 1980 के दशक के मध्य और अंत तक, यह स्पष्ट हो गया था कि सैनिक सरकारों के अब दिन लद चुके हैं। लोकतन्त्रीकरण के उपायों ने उस मानसिकता को बदल दिया जो ब्राज़ील और अर्जेन्टीना पर हावी थी। सैनिक शासनों ने समर्थन हासिल करने के लिए आक्रामक रूख अपना लिया, जिसकी आवश्यकता लोकतांत्रिक निर्णय अधिक होने के साथ ही कम हो गई।

विशेषकर 1985 के बाद के दौर में, इस नवजात लोकतन्त्रीकरण को विदेश नीति के उपायों के माध्यम से बचाना आवश्यक हो गया था, और यह कदम क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में सहायक साबित हुआ। यह स्पष्ट था कि लोकतन्त्र के शत्रु अभी भी थे और एक सामूहिक क्षेत्रीय प्रयास ही उन्हें पराजित कर सकता था। किन्तु यहाँ एक प्रावधान आवश्यक होगा। ब्राज़ील में (अर्जेन्टीना में भी कुछ अंश तक) सेना समय के साथ बदल गई, और अर्जेन्टीना के साथ फिर से सम्बंध मधुर होने की स्थिति सेना की सहमति से ही बनी।

इस प्रकार एक लोकतांत्रिक पहचान इस क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग का आधार बनी। आर्थिक समझौतों से पैराग्वे और चिल्ली जैसे अलोकतांत्रिक शासनों को अलग रखने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था।

क्षेत्र के देशों में आपस में व्यापार और निवेश घटने से भी, 1980 के दशक के अंत तक, राज्य-प्रायोजित उपायों की स्थिति बनी। इसकी परिणति मार्च 1991 की आसूनस्यों की संधि में हुई।

इस संधि पर उरुग्वे, अर्जेन्टीना, पैराग्वे और ब्राज़ील ने हस्ताक्षर किए। मरकोसुर (MERCOSUR) के नाम से जानी गई यह संधि नवम्बर 1991 में प्रभावी हुई। क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में यह एक सबसे बड़ा कदम था।

क्षेत्रीय प्रगति की धुरी बनने वाला दूसरा प्रमुख क्षेत्रीय समुदाय ऐंडियन समझौते के फलस्वरूप गठित हुआ, जिसमें बोलिविया, कोलोम्बिया, इक्वाडोर, पेरू और वेनेज़ुएला शामिल हुए। यद्यपि इसकी स्थापना को तीन दशक हो चुके हैं, फिर भी यह घरेलू और भूमंडलीय दोनों ही किस्म की आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त है, और सत्तर और अस्सी के दशकों में यह स्थिति अधिक रही है। प्रशुल्क के

उदारीकरण पर इसके प्रोटोकॉल के सदस्य राज्यों के नहीं मानने से भी कामों में बाधा पहुँची है। किन्तु अस्सी के दशक के मध्य से, मुक्त क्षेत्रीयतावाद के दृष्टिकोण के माध्यम से, ऐंडियन समझौते ने कुछ लाभ प्राप्त किए है। नब्बे के दशक में, एक मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण और साझा बाहरी प्रशुल्क (टैरिफ) का कम होना महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ रही हैं।

ऐंडियन समझौते के प्रावधानों को सदस्य राज्यों ने कानूनी समर्थन दिया है, और इससे इन अर्थव्यवस्थाओं के निगमों में विश्वास बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप, क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की बाढ़-सी आ गई है।

मरकोसुर की उपलब्धियों और विफलताओं की चर्चा आगे की गई है। अभी तक हमने लैटिन अमेरिकी क्षेत्र तक सीमित क्षेत्रीय एकीकरण पर गौर किया है। आगे हम समूचे पश्चिमी गोलार्ध में क्षेत्रीय एकीकरण पर गौर करेंगे, और इस सम्बंध में हम तीन प्रमुख पहलों की संक्षेप में पड़ताल करेंगे- अमेरिकी राज्य संगठन (Organisation of American States - OAS), उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र - नाफ्ता (North American Free Trade Area – NAFTA) और प्रस्तावित अमेरिकास मुक्त व्यापार संधि (Free Trade Area of the Americas – FTAA)।

लैटिन अमेरिका में 1960 और 1970 के दशकों में क्षेत्रीय एकीकरण के जो उपाय किए गए उनका उद्देश्य 1980 और 1990 के दशकों में उठाए गए कदमों से भिन्न था। पहले की अवधि में, क्षेत्रीयतावाद की आड़ में लागू की गई नीतियाँ अधिकतर संरक्षणवादी और अंतर्मुखी थीं। इसके विपरीत, अभी हाल के प्रस्ताव व्यापार और निवेश में उदारवादी आर्थिक कार्यक्रम की लीक पर रहे हैं। इन क्षेत्रीय समझौतों का उपयोग इस तरह की नीतियों को ठोस रूप देने और समझौते से बाहर जाने की कीमत को बहुत ऊँचा करने के लिए किया गया है।

16.3.1 मरकोसुर

मरकोसुर अर्थात दक्षिणी अमेरिकी साझा बाज़ार की स्थापना क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में दशकों से चल रहे प्रयासों की परिणति थी। साठ के दशक में लैटिन अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन (लाफ्ता) और सत्तर के दशक में केन्द्रीय अमेरिकी साझा बाज़ार और ऐंडियन समझौता सदस्य देशों के आपसी मतभेदों और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी बाहरी शक्तियों के साथ मतभेदों के कारण विफल हो गए।

आर्थिक सहयोग के लिए नया प्रयास अर्जेन्टीनी-ब्राज़ीली आर्थिक एकीकरण कार्यक्रम (Argentine-Brazilian Economic Integration Prograinme – ABEIP) के माध्यम से 1986 में हुआ। दक्षिणी अमेरिका के इन दो बड़े देशों ने अपनी ऐतिहासिक शत्रुता को पीछे छोड़ते हुए आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य इन दोनों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से व्यापार को विविधता प्रदान करना था। किन्तु, दशक के अंत तक आते-आते यह कार्यक्रम काम नहीं कर रहा था। दोनों देशों की घरेलू आर्थिक नीतियाँ काम नहीं कर रही थीं और विदेशी घरेलू कर्ज़ के कारण बने बाहरी आर्थिक दबावों के चलते विकास और उदारीकरण की नीतियों को ताक पर रखना पड़ा था। आर्थिक एकीकरण की परियोजना के लिए यह एक अस्थायी झटका था।

दोनों देशों में सत्ता बदलने से आर्थिक एकीकरण के कार्यक्रम को जारी रखने की प्रक्रिया तेज़ हो गई, जिसकी बहुत ज़रूरत भी थी। इस बार अंतर यह रहा कि आर्थिक एकीकरण के कार्यक्रम को पूर्णता देने के लिए घरेलू आर्थिक सुधार लागू किए गए। क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में पहले के प्रयासों की विफलता का एक कारण यह भी था। इसके लिए कुछ आर्थिक खुलापन ज़रूरी था, और यह उस

संरक्षणवादी कार्यक्रम के विपरीत था जिसका अनुसरण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अधिकांश लैटिन अमेरिकी देश कर रहे थे।

सत्ता में आने के तुरन्त बाद, दोनों नए राष्ट्रपतियों कार्लोस मेनेम (अर्जेन्टीना) और फर्नान्डो कोलर डि मेला (ब्राज़ील) ने (जुलाई 1990 में) ब्यूनस आयर्स अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। इस अधिनियम में 1994 तक एक साझा बाज़ार की स्थापना की माँग की गई थी। उसके एक महीने बाद, पैराग्वे और उरुग्वे भी इस संधि में शामिल हो गए। अंततः मार्च 1991 में, अर्जेन्टीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, और उरुग्वे ने आसूनस्यों की संधि पर हस्ताक्षर किए। आसूनस्यों संधि से ही दक्षिणी अमेरिकी साझा बाज़ार (मरकोसुर) का जन्म हुआ।

मरकोसुर के प्रावधान पहले की संधियों से बिल्कुल हटकर थे। अर्जेन्टीनी-ब्राज़ीली आर्थिक एकीकरण कार्यक्रम की तरह प्रशुल्क में क्षेत्र के अनुसार कटौती करने के बजाय सभी सदस्य देशों के लिए कटौती की गई है। बृहत् आर्थिक नीतियों का तालमेल प्रशुल्क कटौती के इस प्रस्ताव के साथ किया गया है। इसके अतिरिक्त, बाहरी व्यापारिक भागीदारों के लिए एक साझा बाहरी प्रशुल्क का भी प्रस्ताव था। इसका उद्देश्य मरकोसुर के सदस्य देशों की प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाना था।

मरकोसुर का गठन सुरक्षा और आर्थिक दोनों कारणों से किया गया था। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, अर्जेन्टीना और ब्राज़ील के बीच सैन्यवाद और शत्रुता ने क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों को कमज़ोर कर दिया था। दोनों ही देशों की सुरक्षा चिंताआं ने उन्हें आपस में सहयोग नहीं करने दिया। किन्तु अस्सी के दशक के अंत तक स्थिति इतनी बदल गई थी कि सुरक्षा चिंताओं ने गतिशीलता की राह परस्पर विपरीत कर दी।

फॉकलैण्ड-युद्ध में अर्जेन्टीना की पराजय, लोकतांत्रिक शासन की ओर संक्रमण, और महाद्वीप में परमाणु हथियारों के घटते महत्व ने सुरक्षा के मुद्दों को बदलने में मदद की। सुरक्षा की अवधारणा कम विवादजनक थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में गृह युद्ध को रोकना और लोकतन्त्र को बढ़ावा देना; साथ ही, नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध आप्रवास जैसे नए सुरक्षा-मुद्दों से लड़ना भी था। मरकोसुर ने इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है।

अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के बीच एक अटूट सम्बंध भी बन गया है और इसने मरकोसुर के सुरक्षा-सम्बंधी कार्यक्रम को और भी मुखर कंर दिया है। विश्व में अधिकाधिक व्यापारिक गुट बन रहे हैं और इससे दूसरे क्षेत्रों और देशों में असुरक्षा की भावना बन रही है। लैटिन अमेरिका भी इसका अपवाद नहीं है। नाफ्टा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र बना दिया था, वहीं यूरोपीय संघ ने अपना अलग आर्थिक क्षेत्र बना लिया है। आजकल विश्व-अर्थव्यवस्था से अलग-थलग होने का मतलब होता है ढीली-ढाली अर्थव्यवस्था और यही राजनीतिक असंतोष का रूप ले लेती है। अब क्योंकि लैटिन अमेरिका में लोकतन्त्र ही शासन का आधार है, तो वहाँ आर्थिक उथल-पुथल के राजनीतिक और सामाजिक परिणाम भी होंगे। अर्जेन्टीना में यह स्पष्ट रूप में देखने में आया है, जहाँ पिछले दो वर्षों में अर्थव्यवस्था नीचे आ गई है।

अस्सी के दशक के अंतिम वर्षों से अर्जेन्टीना और ब्राज़ील की सरकारें जिन नव-उदारवादी नीतियों का अनुसरण कर रहीं थीं वे क्षेत्रीय एकीकरण में अधिक सहायक थीं, और इन पहलों से उनके कार्यक्रम को सचमुच उछाल मिला था। उनकी घरेलू आर्थिक नीतियों का केन्द्र व्यापारिक उदारवाद था, जिसका उद्देश्य तुलनात्मक लाभ की उपलब्धियों को बढ़ाना और परिणाममूलक सुलाभ (बड़े पैमाने की किफायतों) की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करना था। किन्तु, बड़े घरेलू बाज़ारों के अभाव में, लैटिन अमेरिकी देशों को विदेशों की ओर देखना पड़ रहा है, और क्षेत्रीय एकीकरण की भूमिका यहीं इतनी

महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे वे अधिक बड़े बाज़ारों तक पहुँचने और अधिक मात्रा में व्यापार पाने में समर्थ हो जाते हैं, और विशेषज्ञता प्राप्त करने में और भी सक्षम होते हैं।

बाज़ार में सक्रिय पात्रों के लिए भी, मरकोसुर के माध्यम से हुए राष्ट्रीय एकीकरण ने लैटिन अमेरिका को निवेश का एक अधिक आकर्षक क्षेत्र बना दिया है। बाज़ारों और बुनियादी सुविधाओं के एकीकरण के चलते निगम भी अब अपनी विशेषज्ञता और तुलनात्मक लाभों के अनुसार देशों में निवेश करने की स्थिति में हैं।

16.4 गोलार्ध एकीकरण

16.4.1 उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र (नाफ्टा)

गोलार्द्ध की राजनीति में जो एक स्वरूप बार-बार उभरा है, वह है संयुक्त राज्य अमेरिका की संलिप्तता और प्रभाव। 1992 में उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र - नाफ्टा (North American Free Trade Area – NAFTA) के बनने और 'अमेरिकी राज्य संगठन' (Organisation of American States) के काफी समय से अस्तित्व में होने से इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की संलिप्तता को औपचारिक रूप मिल गया।

इसके नाम के विपरीत, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र मात्र एक मुक्त व्यापार क्षेत्र ही नहीं है। इसमें निवेश, निजीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार, श्रम मानक और परिवेश जैसे अनेक क्षेत्रों पर विनियम और साझा मानक शामिल हैं। उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे गोलार्ध मुक्त व्यापार क्षेत्र अर्थात् अमेरिकास के मुक्त व्यापार क्षेत्र की ओर एक कदम के रूप में देखा जा सकता है।

उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र का उदय क्षेत्रीय एकीकरण को नियंत्रित और निर्देशित करने के राज्यों के प्रयासों के फलस्वरूप हुआ। यह उन गहन आर्थिक सम्बंधों को औपचारिक रूप देने का प्रयास था जो अस्सी के दशक के मध्य तक विशेषकर 1986 में मैक्सिकी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ इस क्षेत्र में बन चुके थे। इसका गठन मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं को हमेशा के लिए जोड़ने और संयुक्त राज्य अमेरिका को और अधिक उदारीकरण की राह पर अग्रसर करने के लिए भी था।

इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र (नाफ्टा) पूंजी निवेश के अत्यंत व्यापक क्षेत्रों को लेकर चलता है, और इस प्रयास में रहता है कि निवेश के अवरोधों को कैसे समाप्त किया जा सकता है। तेल, गैस और मीडिया जैसे कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय नियंत्रण को बनाकर रखा गया था। ऑटोमोबाइल क्षेत्र जैसे अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में, उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र के विनियम लागू होने से पहले समायोजन की एक अवधि निश्चित की गई थी।

यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि नाफ्टा ने संयुक्त राज्य अमेरिका - मैक्सिको सम्बंध की बुनियादी विशेषताओं को नहीं बदला। दोनों देशों की परस्पर निर्भरता हमेशा उत्तरी सहभागी के पक्ष में संतुलित रही है। नाफ्टा ने तो केवल इसे औपचारिक रूप प्रदान किया है। किन्तु इसे ऐसी प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखा गया था जिससे एक को लाभ होने से अन्य को नुकसान होता है। सापेक्ष लाभों की जगह, इसमें सभी पक्षों के लिए पूर्ण लाभ का उद्देश्य रखा गया था। इसके पीछे विचार यह था कि विषमानुपाती एकीकरण होने के बावजूद मैक्सिको विदेशी निवेश के आगमन और उत्तरी अमेरिकी बाज़ारों तक अधिक पहुँच के माध्यम से फिर भी बहुत फायदे में रहेगा।

किन्तु 1994-95 में मैक्सिको में जो मुद्रा का संकट बना, वह नाफ्टा के उद्देश्यों के लिए एक बड़ा झटका था। नाफ्टा और आर्थिक उदारीकरण ने मैक्सिको को नब्बे के दशक के प्रारंभ में विदेशी निवेश के लिए एक अत्यधिक आकर्षक केन्द्र बना दिया था। लग रहा था कि विदेशी पूंजी के आने से मैक्सिको त्वरित विकास की राह पर बढ़ रहा है। किन्तु आर्थिक संकट और पैसों के अवमूल्यन के चलते विदेशी निवेशकों ने अपने हाथ खींच लिए। इससे यह स्पष्ट हो गया कि विनिमयित बाज़ारों के अभाव में अस्थिर और अनिश्चित विदेशी पूंजी पर निर्भर करना कितना जोखिम का काम था। तब से यह लैटिन अमेरिकी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण सबक रहा है।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने 20 अरब (billion) डॉलर की एकमुश्त सहायता देकर मैक्सिको को इस संकट से निकाला था। किन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि यदि प्रस्तावित अमेरिकास मुक्त व्यापार संधि (FTAA) अस्तित्व में आ गयी तब भी क्या भविष्य में ऐसा संकट आने पर उसे और क्षेत्र के अन्य देशों को ऐसी ही सहायता दी जाएगी।

एक और समस्या जिससे नाफ्टा ग्रस्त है और जो लैटिन अमेरिका के क्षेत्रीय एकीकरण के मुद्दों से संबंधित है, वह है वितरण सम्बंधी टकराव की समस्या। पिछले दशक में नाफ्टा के तीनों सदस्य देशों में आय की असमानता बढ़ गई है। इस स्थिति व, चलते इन देशों में आय की असमानता बढ़ गई है। इस स्थिति के चलते इन देशों के अधिकांश कामगार तबकों ने नाफ्टा को अधिक विस्तार अथवा महत्व देने का विरोध करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, समान मानक लागू करने का विवाद भी जारी है। समान अथवा साझा मानकों में वे मानक आते हैं जो मज़दूरों के अधिकारों की मज़बूती और पर्यावरण के संरक्षण से जुड़े हैं।

किन्तु तमाम टकरावों और विवादों के बावजूद, मैक्सिको को तो नाफ्टा से बहुत फायदा हो रहा है। 1990 से, इसका कुल व्यापार अस्सी के पूरे दशक की तुलना में 60 प्रतिषत बढ़ गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसका व्यापार 1986 से 400 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है।

16.4.2 अमेरिकास का मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTAA)

अमेरिकास के मुक्त व्यापार क्षेत्र (FTAA) के लिए बातचीत की शुरुआत अप्रैल 1998 में हुई थी। अमेरिकास के मुक्त व्यापार क्षेत्र से पहले अमेरिकास पहल उद्यम (Enterprise of the Americas 'Initiative – EAI) का अस्तित्व था।

अमेरिकास के मुक्त व्यापार क्षेत्र में कम से कम 34 देश होंगे। किन्तु इसके गठन की प्रक्रिया निर्विवाद नहीं रही है।

अमेरिकास के मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना में एक बाधा यह है कि इस क्षेत्र में उपक्षेत्रीय संगठनों और समझौतों की गहरी पैठ है, और इस बात को लेकर भी भ्रम है कि अमेरिकास के मुक्त व्यापार क्षेत्र उनके साथ कैसे समायोजन करेगा। फिर, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में जारी अस्थिरता और सरकारों में राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अमेरिकास के मुक्त व्यापार क्षेत्र 2005 की अपनी उस अंतिम समय-सीमा तक प्रभावी हो भी पाएँगे या नहीं जिसकी घोषणा मायमी में 1994 में संपन्न अमेरिकास (उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकी) के शिखर सम्मेलन में की गई थी।

गोलार्ध मुक्त व्यापार क्षेत्र का विचार सबसे पहले राष्ट्रपति बुश ने रखा था। आम योजना यह थी कि इसमें क्षेत्र के सभी उप-क्षेत्रीय व्यापार समूहों को शामिल किया जाएगा। गोलार्ध क्षेत्रीयतावाद भी मरकोसुर और ऐंडियन संधि की तरह उपक्षेत्रीय गुटों की कार्य प्रणाली पर प्रभाव डालता। स्थिति

इसलिए और भी जटिल हो जाती है क्योंकि गोलार्ध क्षेत्रीयतावाद का प्रभाव अलग उप-क्षेत्र पर अलग होगा और लैटिन अमेरिका के प्रत्येक देश को वह एक भिन्न प्रकार से प्रभावित करेगा।

एक और बुनियादी मुद्दा है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं का ज़बरदस्त अंतर। संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था के कई तबकों, विशेषकर कामगारों को अमेरिकास के मुक्त व्यापार क्षेत्र के प्रावधानों पर आपत्ति है। उनके लिए तो यह नौकरी गंवाने का सबब होगा, क्योंकि लैटिन अमेरिकी कम्पनियाँ – उत्तरी अमेरिकी बाज़ारों में आएँगी तो उनके साथ मज़दूर भी होंगे जो अपने अमेरिकी भाइयों की तुलना में बहुत कम वेतन पर काम करने को राज़ी रहते हैं। वास्तव में, अवैध आप्रवासन अमेरिकी राजनीति का एक विवादास्पद मुद्दा है। यदि उन्हीं बाज़ारों के लिए और अधिक कंपनियाँ प्रतिस्पर्धा करेंगी तो निगमों के आकार में कटौती और भी बढ़ जाएगी।

फिर भी, अमेरिकास के मुक्त व्यापार क्षेत्र के प्रस्तावों में क्षेत्र की आर्थिक प्रक्रियाओं के लगभग प्रत्येक पहलू को शामिल किया गया है। इसके नौ वार्ता समूह बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, निवेश सेवाओं, प्रतिस्पर्धा नीति, बाज़ार तक पहुँच, कृषि अनुदान, ऐंटी-डंपिंग, प्रतिकारी शुल्कों, सरकारी अधिप्राप्ति (procurement) और विवादों के निपटारे को देखते हैं।

इन वार्ताओं का विरोध मरकोसुर के अनेक देशों ने किया है। उनका दृष्टिकोण यह है कि क्षेत्र के मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों को ही मज़बूत किया जाना चाहिए। वे यह भी सोचते हैं कि अमेरिकास के मुक्त व्यापार क्षेत्र पर नाफ्टा के नमूने को थोपा जा सकता है, जबकि इसे ऐसे नमूने पर आधारित होना चाहिए जो लैटिन अमेरिका के अधिक अनुकूल है।

16.4.3 अमेरिकी राज्यों का संगठन (OAS)

अमेरिकी राज्यों का संगठन (Organisation of American States – OAS) एक सबसे पुराना गोलार्ध संगठन है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसकी जड़ें उस अंतर-अमेरिकी व्यवस्था में है जो पिछली शताब्दी के प्रारंभ में अस्तित्व में आई थी। अंतर-अमेरिकी व्यवस्था के मूल में वह अखिल अमेरिका का विचार था जिसका उदय 1880 के दशक में हुआ था। इसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्यापार बढ़ाने और विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए किया था। यह अन्तर्राष्ट्रीय समानता और सहयोग के सिद्धान्तों पर आधारित था। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत से द्वितीय विश्व युद्ध तक संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका के आपसी रिश्ते मनरो सिद्धान्त और अखिल अमेरिकावाद के बीच झूलते रहे। किन्तु इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच एक अंतर्निहित अंतर्विरोध था, जिसकी जड़ें आज भी देखी जा सकती हैं।

अमेरिकी राज्यों का संगठन इस मायने में अनूठा है कि यह पहला क्षेत्रीय संगठन था जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणापत्र के तत्वावधान में की गई थी। 21 संस्थापक सदस्यों से बढ़कर आज इसकी सदस्य संख्या 35 हो गई है। इसकी स्थापना पश्चिमी गोलार्ध में शान्ति, सहयोग और समझ को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका और लैटिन अमेरिका के पारम्परिक आपसी मतभेदों के चलते 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक के प्रारंभ तक अमेरिकी राज्यों का संगठन निष्प्रभावी हो गया। केन्द्रीय अमेरिका की कलह और गृह-युद्ध, और 1982 का फॉकलैण्ड युद्ध इस ऊहापोह के कुछ कारण थे।

शीत युद्ध की समाप्ति के साथ यह क्षेत्र नए सिरे से आर्थिक आकर्षण का केन्द्र बना। सैनिक शासनों की भी विदाई हो रही थी। इस स्थिति ने अमेरिकी राज्यों का संगठन के पारम्परिक सुरक्षा-उन्मुख दृष्टिकोण को प्रभावित किया।

किन्तु लोकतन्त्र को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के बाद अमेरिकी राज्यों के संगठन को जीवनदान मिल गया है। अस्थिर लोकतन्त्र के इतिहास वाले इस क्षेत्र के शासनों को एक स्वतंत्र सरकार का महत्व समझ में आ गया है, और वे लोकतन्त्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देने के प्रयास में जुट गए हैं। 1991 के 'सेन्टियागो कमिटमेंट' में महाद्वीप में लोकतन्त्रीकरण की प्रक्रिया को समर्थन देने का वादा किया गया है, और यह संकल्प भी किया गया है कि इस प्रक्रिया में आने वाली किसी भी बाधा से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएँगे और स्थिति को संभाला जाएगा।

इस सम्बंध में इसकी गतिविधि के उदाहरण हैं हेटी में 1991 में हुए तख्ता पलट के बाद वहाँ लोकतन्त्र की बहाली के लिए अभियान चलाना और पेरू में अल्बर्टो फ्यूजीमोरी के शासन में लोकतन्त्र के लिए खड़ी की गई बाधाओं को दूर करना। अभी हाल में, इसने अप्रैल 2002 में थोड़े समय के तख्ता पलट के बाद ह्यूगो चावेस की बहाली में भी मदद की है।

इससे अमेरिकी राज्यों संगठन के लक्ष्यों के विरोधाभास भी उज़ागर होते हैं। इसके अधिकांश सदस्य अहस्तक्षेप की नीति बनाए रखना चाहते हैं, किन्तु वे लैटिन अमेरिका के नवजात लोकतन्त्र को भी बचाना चाहते हैं। अनेक राज्य हस्तक्षेप के तर्क को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए हस्तक्षेप के बहाने के रूप में देखते हैं।

सुरक्षा और लोकतंत्र को बचाए रखने के अमेरिकी राज्यों के संगठन के लक्ष्य तो प्रशंसनीय हैं किन्तु क्षेत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्याओं को हल कर पाने में इसकी विफलताएँ भी गंभीर हैं। फॉकलैण्ड का संकट और क्यूबा की समस्या इन विसंगतियों का उदाहरण हैं जो तब पैदा होती हैं जब बाहरी शक्तियों के हित अपार रुकावट बन जाते हैं।

16.5 सारांश

लैटिन अमेरिका क्षेत्रीय एकीकरण के बल पर आर्थिक विकास की राह पर चल पड़ा है। वास्तव में, समाधान तो इस प्रश्न का होना है कि एकीकरण के कार्यक्रमों में से कौन-सा कार्यक्रम कारगर रहेगा।

अभी तो स्थिति यह है कि मरकोसुर और नाफ्टा की सीमाएँ अलग-अलग हैं, किन्तु नाफ्टा के विस्तार और अमेरिकास के मुक्त व्यापार क्षेत्र के गठन से लाभों के वितरण और प्रक्रियाओं और अधिकार-क्षेत्र को लेकर कुछ गंभीर विवाद खड़े हो जाएँगे।

एक और बाधा आम जनता की ओर से आ सकती है। जब तक समाज के निचले तबके की हालत नहीं सुधरती, क्षेत्रीय एकीकरण संगठनों के खिलाफ गुस्सा और असंतोष बना रहेगा, क्योंकि उन्हें इस बदहाली के कारण के रूप में देखा जाएगा।

किन्तु, अभी तो क्षेत्रीय संगठन लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के लिए मुक्त बाज़ार पूंजीवाद की अनिश्चितताओं के प्रति ढाल का काम कर रहे हैं।

लैटिन अमेरिकी देशों की अनेक विशेषताएँ हैं जिनसे हमें इसे एक एकीकृत क्षेत्र के रूप में देखने का अवसर मिलता है। आर्थिक दृष्टि से, ये विकासशील देश हैं जिनका हिस्सा विश्व व्यापार में बहुत कम है, और जो कृषि और खनन जैसे प्राथमिक उत्पादों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी यह क्षेत्र अस्थिर रहा है। इन्हीं समान स्थितियों के चलते ये देश आर्थिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर एकजुट हुए हैं, जिससे विकसित देशों की तुलना में उनकी स्थिति अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर अधिक अच्छी हो।

पारम्परिक आर्थिक समूहों को लैटिन अमेरिका में निस्संदेह विफलता ही हाथ लगी है – चाहे वह लैटिन

अमेरिकी मुक्त व्यापार संगठन हो, केन्द्रीय अमेरिकी साझा बाज़ार हो, अथवा कैरिकॉम। लैटिन अमेरिकी देशों के एक राजनीतिक समूह कांटाडोरा भी अधिक सफल नही हुआ। इन पारम्परिक समूहों के स्थान पर एक नए क्षेत्रीयतावाद का उदय 'मरकोसुर' के रूप में हुआ है। नया क्षेत्रीयतावाद इस मायने में भिन्न है कि यह भूमंडलीकरण की शक्तियों के अनुरूप है। भूमंडलीकरण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि अलग-अलग राज्य की आर्थिक नीतियाँ तय करते समय भूमंडलीय अर्थव्यवस्था में उनकी स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। राजनीतिक मंच पर एक और विशुद्ध लैटिन अमेरिकी पहल 'रियो समूह' ने कुछ आशाएँ बंधाईं, किन्तु इसे अभी भी अपनी योग्यता सिद्ध करनी है।

एक और घटनाक्रम रहा गोलार्ध एकीकरण की प्रक्रिया, जो इस क्षेत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव के परिणामस्वरूप शुरू हुई। 'नाफ्टा' इसी प्रयास का फल है। किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका मुक्त व्यापार क्षेत्र को अमेरिकास मुक्त व्यापार संधि (FTAA) के रूप में समस्त अमेरिकास (उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका) में फैलाना चाह रहा है। अमेरिकी राज्यों का संगठन (OAS) गोलार्ध का एक सबसे पुराना राजनीतिक समूह है, किन्तु अमेरिकी राज्यों के संगठन के लक्ष्य अभी भी अस्पष्ट हैं और सभी लैटिन अमेरिकी देश इसके निर्णयों से खुश नहीं हैं।

16.6 अभ्यास प्रश्न

1) लैटिन अमेरिका में क्षेत्रीयतावाद के विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

2) लैटिन अमेरिका में पारम्परिक क्षेत्रीय गुटों का पतन किन कारणों से हुआ?

3) नए क्षेत्रीयतावाद से आप क्या समझते हैं?

4) मरकोसुर और नाफ्टा में क्या अंतर है? आप इनमें से किसे अधिक उपयोगी मानते हैं?

5) क्षेत्रीय गुटों (समूहों) से सदस्य देशों को क्या लाभ होता है?